(ग) क्या भूमि को कब्जे में लेने और अधिग्रहण की अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए भी स्थानीय किसानों/ भू-स्वामियों को मुआवजा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पट्टी पालचन और बाखा पालचन सहित कुछ गांवों में निजी भूमि के अधिग्रहण और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को रक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में सरकार की स्वीकृति 26.2.1991 को जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है।

भू-स्वामियों को सेना द्वारा भूमि को कब्जे में लिए जाने की तारीख अर्थात् 1.7.1988 से 31.12.1991 तक, 64,417 रुपये प्रति वर्ष की दर से किराए के रूप में कुल 2,25,459 रुपये के मुआवजा की अदायगी कर दी गई है।

किराए के रूप में भूमि के मुआवजे की अदायगी तब तक की जाती रहेगी जब तक कि भूमि का अधिग्रहण औपचारिक रूप से नहीं कर लिया जाता। सरकार ने कोठी पालचन में कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की है।

**अमरीका के साथ सैनिक समझौता**

**4004. श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका के साथ कोई सैनिक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सैनिक समझौता किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**Private enterprises to manufacture defence materials**

4005. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are planning to promote private enterprises in the manufacturing of materials needed for defence; and

(b) whether such proposal would include the participation of multinational companies ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) In order to achieve a high degree of self reliance, Government's policy is to make optimum use of the national industrial infrastructure. Pursuant to this policy, capacities available in the civil sector both in the private and the non-defence public sectors are being utilised for production of defence stores.

(b) There is no bar to utilise the capacity available with, the Indian Units of multinational companies so far as production of non-lethallnon-sentitive defence, atores is concerned.

**Training to foreign airmen**

4006. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of DEFENCE foe pleased to state:

(a) whether any training is being provided by Indian Airfbrce to the airmen of various foreign countries;